देश के कई राज्यों में बारिश का कहर, बाढ़ के हालात

प्रयागराज में पांच फीट तक भरा पानी, उत्तराखंड में चार लोगों की मौत; दिल्ली-एनसीआर में भी जलभराव

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में नदी-नाले उफान पर हैं। सतना में भारी बारिश के कारण चित्रकूट की गुप्तगोदावरी में जलस्तर बढ़ गया है। डिंडौरी में नदी-नाले उफान पर होने से 12 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है। पन्ना के कई गांवों में भी बारिश का पानी भर गया है।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पिछले चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले तीन दिनों में यहां 205 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शहर के कई इलाकों में पांच फीट तक पानी भर गया है। घरों और छात्रावासों में पानी घुसने से बुधवार को करीब 2000 छात्रों को छात्रावास छोड़ना पड़ा। मौसम विभाग ने प्रदेश के नौ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों के किनारे स्थित 100 से अधिक मंदिरों में पानी प्रवेश कर गया है। हरिश्चंद्र घाट की गलियों और सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है, जबकि मणिकर्णिका घाट पर छत पर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश से जुड़ी घटनाओं में बुधवार को चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो साल का बच्चा और दिल्ली की 25 वर्षीय महिला भी शामिल है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के कारण 88 सड़कें बंद हो गई हैं।

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह तेज बारिश हुई। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी। द्वारका अंडरपास और एयरपोर्ट रोड समेत कई स्थानों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

बिहार में भी बारिश और बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के कारण गंडक नदी उफान पर है। बगहा में नदी के कटाव से एक स्कूल नदी में समा गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बाढ़ का पानी पांच गांवों तक पहुंच गया है। असम के गुवाहाटी में तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। वहीं जोनाई क्षेत्र में पहले पुल टूटने के बाद बच्चों को नाव से नदी पार कर स्कूल जाना पड़ रहा है। झारखंड के हजारीबाग समेत कई इलाकों में भी लगातार बारिश से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कनहर बांध का जलस्तर बढ़कर 263.1 मीटर पहुंच गया। इसके बाद बांध के 14 गेट खोल दिए गए।

लद्दाख में महिला पर्यटक की सेना पर टिप्पणी से विवाद, पूर्व सैन्य अधिकारियों ने जताई नाराजगी

नईदुनिया ब्यूरो, लद्दाखः लद्दाख के करगिल जिले में सुरक्षाबलों और एक महिला पर्यटक के बीच बहस का वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। वीडियो में महिला मिनामार्ग चेकपॉइंट पर कुछ समय के लिए सड़क बंद किए जाने का विरोध करती नजर आ रही है। वह सुरक्षाबलों से पर्यटकों को रोके जाने का कारण पूछती है और इसकी तुलना कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों से करती है। वीडियो में महिला यह कहते हुए भी सुनाई दे रही है कि सेना के जवानों को मिलने वाला वेतन लोगों के टैक्स से आता है। उसने खुद को नई पीढ़ी से बताते हुए इस तरह की व्यवस्था पर आपत्ति जताई। सेना के अधिकारियों ने मौके पर महिला को समझाने का प्रयास किया। महिला की टिप्पणी के बाद पूर्व सैन्य अधिकारियों ने जवानों का बचाव करते हुए नाराजगी जताई। मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कहा कि देश की रक्षा कर रहे जवानों को गलत तरीके से दोषी ठहराना या उनका अपमान करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आलोचना तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। पूर्व चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने कहा कि सैनिक वेतन प्राप्त करने से पहले ही कर देते हैं। उन्होंने लोगों से जवानों का सम्मान करने और कानून का पालन करने की अपील की। पूर्व चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने कहा कि सेना की सैलरी को लेकर की गई टिप्पणी सैनिकों के बलिदान को कमतर दिखाती है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी महिला के नई पीढ़ी से जुड़े बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि किसी कथित अपमान के मामले में पूरी पीढ़ी की पहचान को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करने से नई पीढ़ी की छवि प्रभावित होती है। मिनामार्ग नियंत्रण चौकी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास संवेदनशील और ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है। सुरक्षा कारणों से यहां सड़क की आवाजाही को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जाता है।

आप के तीन और घोटाले उजागर करने सुकेश की धमकी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एक नई चिट्ठी लिखी है। गुरुवार को सामने आई इस चिट्ठी में सुकेश ने पार्टी से जुड़े तीन और कथित घोटालों तथा भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा करने की धमकी दी है। सुकेश ने दावा किया कि दिल्ली शराब नीति और जल बोर्ड से जुड़े मामलों को लेकर उसके पहले किए गए खुलासे सही साबित हुए हैं। उसने कहा कि अब आम आदमी पार्टी से जुड़े तीन अन्य विभागों में कथित घोटाले और भ्रष्टाचार उजागर किए जाएंगे। उसने पंजाब को लेकर भी चेतावनी दी और कहा कि वहां पार्टी के खिलाफ और अधिक गुस्सा देखने को मिलेगा। चिट्ठी में सुकेश ने आम आदमी पार्टी के नाम को लेकर भी टिप्पणी की। उसने कहा कि उसके लिए पार्टी का मतलब घोटालों से जुड़ी पार्टी है। उसने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को संबोधित करते हुए कहा कि उसे सब कुछ याद है और वह जल्द ही उन्हें चौंकाएगा। सुकेश इससे पहले भी आप नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगा चुका है।

जापान के पास 5,500 परमाणु बम बनाने जितना प्लूटोनियम होने का चीन का दावा

चीनी राजदूत बोले- टोक्यो के पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता, लेकिन जापान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं

बीजिंग, एजेंसीः चीन ने जापान की परमाणु क्षमता को लेकर चिंता जताते हुए दावा किया है कि उसके पास करीब 44.4 टन अलग किया हुआ प्लूटोनियम है। रूस में चीन के राजदूत झांग हानहुई के अनुसार, इतनी मात्रा से सैद्धांतिक तौर पर करीब 5,500 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि जापान के पास इतने परमाणु हथियार मौजूद हैं। यह दावा प्लूटोनियम की मात्रा के आधार पर लगाया गया सैद्धांतिक अनुमान है।

झांग ने रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास को दिए साक्षात्कार में कहा कि जापान के पास इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा संसाधित कर उससे प्लूटोनियम अलग करने की तकनीक है। 2024 के अंत तक जापान के पास करीब 44.4 टन अलग किया हुआ प्लूटोनियम होने का दावा किया गया है। इसके अलावा करीब 191 टन प्लूटोनियम इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन में मौजूद बताया गया है।

प्लूटोनियम रेडियोधर्मी तत्व है, जो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के इस्तेमाल के दौरान बनता है। जापान इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा संसाधित कर उससे प्लूटोनियम अलग करता रहा है। इसी कारण कई दशकों में उसके पास प्लूटोनियम का बड़ा भंडार जमा हुआ है।

चीन के राजदूत ने कहा कि जापान परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य है और उसके पास परमाणु हथियार नहीं हैं। हालांकि, अगर जापान भविष्य में परमाणु हथियार बनाने का फैसला करता है तो उसके पास इसके लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता मौजूद हो सकती है। उन्होंने आशंका जताई कि इससे पूर्वोत्तर एशिया में शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है और परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ सकती है।

जापान की परमाणु नीति तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों पर आधारित है। 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ईसाकु सातो ने इनकी घोषणा की थी और 1971 में जापानी संसद ने इन्हें अपनाया। इनके तहत जापान परमाणु हथियार न रखने, न बनाने और उन्हें देश में प्रवेश की अनुमति न देने की नीति पर कायम है।

हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों के बाद जापान में परमाणु हथियारों का लंबे समय से विरोध रहा है।

अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की अरब सागर में एंट्री

250 दिन से तैनात अब्राहम लिंकन की जगह पहुंचा युद्धपोत, नौसैनिकों ने खराब सुविधाओं की शिकायत की

वॉशिंगटन, एजेंसीः अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन ने गुरुवार से अरब सागर में तैनाती शुरू कर दी है। उसने पश्चिम एशिया में 250 दिन से अधिक समय से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह ली है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसकी जानकारी दी है। जॉर्ज वॉशिंगटन की तैनाती ऐसे समय हुई है, जब ईरान को लेकर क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। इससे ईरान के आसपास अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी बढ़ गई है।

यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन इससे पहले दक्षिण चीन सागर में तैनात था। हाल ही में उसने वियतनाम के दा नांग में बंदरगाह पर भी पड़ाव किया था। यह पहली बार नहीं है, जब यह विमानवाहक पोत अरब सागर क्षेत्र में पहुंचा है। 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में भी इसने फारस की खाड़ी में कई सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया था।

इसमें इराक के कुवैत पर हमले के दौरान की गई तैनाती, 1994 का ऑपरेशन विजिलेंट वॉरियर, 1998 का ऑपरेशन डेजर्ट थंडर और 2002 में अफगानिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शामिल हैं।

इस बीच यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात अमेरिकी नौसैनिकों के लंबे समय तक समुद्र में रहने को लेकर भी सवाल उठे हैं। नौसैनिकों के परिवारों ने उनकी स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। जहाज पर खराब शौचालय, फफूंद लगे स्नानघर, दूषित पानी और कई सप्ताह तक गर्म पानी नहीं मिलने जैसी समस्याओं की शिकायतें सामने आई थीं।

एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अब्राहम लिंकन पर तैनात छह अमेरिकी सैन्यकर्मियों ने जहाज से समुद्र में कूदने की कोशिश की थी। यह युद्धपोत करीब नौ महीने से समुद्र में था और ईरान के साथ युद्ध के दौरान बिना किसी बंदरगाह पर रुके लगातार समुद्र में संचालित हो रहा था। इस पर करीब 5,000 अमेरिकी मरीन तैनात हैं।

मानसिक तनाव के साथ जहाज पर उपलब्ध सुविधाओं को लेकर भी शिकायतें सामने आईं। कैलिफोर्निया के सांसद माइक लेविन के अनुसार, एक समय भोजन में केवल आधा कप चावल दिए गए और लंबे समय तक गर्म पानी भी उपलब्ध नहीं था।

किताबों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ तथा नीति लागू करने के तरीके पर भी उठे सवाल

उत्तर-दक्षिण की भाषाएं सीखना देश के लिए अच्छाः सुप्रीम कोर्ट

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू तीन भाषा नीति से जुड़े कई पहलुओं पर सवाल उठाए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने किताबों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर पड़ने वाले बोझ तथा अलग-अलग स्कूलों में नीति लागू करने के तरीके को लेकर सीबीएसई से जवाब मांगा।

सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि क्या यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा कि उत्तर भारत के विद्यार्थी दक्षिण भारतीय भाषाएं सीखें और दक्षिण भारत के विद्यार्थी उत्तर भारतीय भाषाएं सीखें। उन्होंने कहा कि सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए और क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर हीन भावना का माहौल नहीं बनना चाहिए। पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू तीन भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विद्यार्थियों को दो भारतीय मूल भाषाएं पढ़नी होंगी, लेकिन कई स्कूलों में इसके लिए जरूरी किताबें, शिक्षक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अदालत को बताया गया कि स्कूल खुलने के चार महीने बाद भी कुछ संस्थानों में किताबें नहीं पहुंची हैं।

याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने कहा कि बिना बुनियादी अध्ययन सामग्री के विद्यार्थियों से अचानक नई भाषा सीखने की उम्मीद करना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि नई भाषाओं में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता विद्यार्थियों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने स्पष्ट किया कि योजना में केवल आंतरिक मूल्यांकन होगा और नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को अतिरिक्त भाषा में उत्तीर्ण न होने पर रोका नहीं जाएगा।

प्रिंसिपल हत्याकांड में दो छात्र गिरफ्तार

नईदुनिया ब्यूरो, हैदराबादः तेलंगाना के नलगोंडा में स्कूल प्रिंसिपल कल्लू रूपा रेड्डी की हत्या के मामले में पुलिस ने दो छात्रों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, प्रिंसिपल की आखिरी फोन बातचीत में इस्तेमाल किए गए 'बाबू' शब्द से दोनों छात्रों तक पहुंचने में मदद मिली।

दोनों ने पूछताछ में हत्या की बात कबूल की है। रूपा रेड्डी कोंडामल्लेपल्ली के नागार्जुन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल और निदेशक थीं। 12 अगस्त की सुबह उनका शव घर में मिला था। शरीर पर चाकू से 27 वार किए गए थे। पुलिस के अनुसार, दोनों छात्र चोरी के इरादे से उनके घर में घुसे थे। वारदात से करीब पांच दिन पहले उन्होंने घर की रेकी की थी। पहचान छिपाने के लिए चाकू, दस्ताने और मंकी कैप खरीदी थी।

वारदात के दिन एक छात्र मंकी कैप और दस्ताने पहनकर घर में दाखिल हुआ। बेडरूम में करीब ढाई लाख रुपये देखकर वह उन्हें लेकर भागने लगा। इसी दौरान उसकी मंकी कैप खिसक गई और रूपा रेड्डी ने उसे पहचान लिया। पहचान सामने आने के डर से आरोपी ने उन पर चाकू से 27 वार कर दिए। इसके बाद दोनों रुपये लेकर फरार हो गए।

प्रस्ताव *राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का प्रस्ताव, मरीज और अस्पताल भी देख सकेंगे डॉक्टर का डिजिटल रिकॉर्ड...*

डॉक्टरों को मिलेगी एक विशिष्ट पहचान संख्या, कर सकेंगे प्रैक्टिस

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश में पंजीकृत प्रत्येक डॉक्टर को केंद्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान संख्या देने का प्रस्ताव रखा है। इसके लागू होने के बाद डॉक्टर को एक बार राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकरण कराने पर दूसरे राज्य में चिकित्सा प्रैक्टिस के लिए अलग से नया पंजीकरण या लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। प्रस्ताव के तहत डॉक्टरों का राष्ट्रीय डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। इसमें डॉक्टर के पंजीकरण, लाइसेंस की स्थिति और उनके खिलाफ हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी दर्ज होगी। यह रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जिसे मरीज और अस्पताल भी देख सकेंगे।

यह प्रस्ताव डॉक्टरों के पंजीकरण और प्रैक्टिस लाइसेंस से जुड़े 2026 के प्रारूप नियमों में रखा गया है। राज्य चिकित्सा परिषद से पंजीकरण मिलने के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड डॉक्टर को विशिष्ट पहचान संख्या जारी करेगा। इसके बाद डॉक्टर का नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। यही पहचान संख्या देशभर में डॉक्टर की पहचान के रूप में काम करेगी

और उन्हें किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में प्रैक्टिस की अनुमति होगी।

प्रस्ताव के अनुसार, डॉक्टर का प्रैक्टिस लाइसेंस पांच वर्ष तक वैध रहेगा। अवधि समाप्त होने के तीन महीने के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने पर डॉक्टर का पंजीकरण निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद वह चिकित्सा प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा और इसकी जानकारी राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में भी अपडेट की जाएगी। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में डॉक्टर के पंजीकरण, लाइसेंस की स्थिति और अनुशासनात्मक कार्रवाई का रिकॉर्ड रखा जाएगा। यदि किसी डॉक्टर पर चिकित्सकीय लापरवाही, गलत आचरण या पेशेवर कदाचार का मामला सामने आता है, तो संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद इसकी जांच करेगी। किसी दूसरे राज्य की परिषद द्वारा डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर इसकी जानकारी राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर और डॉक्टर के मूल राज्य के चिकित्सा रजिस्टर में भी दर्ज हो जाएगी। नए सिस्टम के तहत एकीकृत अखिल भारतीय पंजीकरण पोर्टल तैयार किया जाएगा। जिन राज्यों में पहले से डिजिटल पंजीकरण की व्यवस्था है, उन्हें राष्ट्रीय पोर्टल से जोड़ा जाएगा। पहले से भारतीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत डॉक्टरों को भी विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। जिन डॉक्टरों के पास अभी यह संख्या नहीं है, उनके लिए एक बार का जानकारी अद्यतन अभियान चलाया जाएगा। डॉक्टर एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड के पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट कर विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।